भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 725

26.06.2019 को उत्तर देने के लिए

एनएसओ द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़े

725. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ के हाल ही के आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सर्वाधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रोजगार के आंकड़े सरकार के लिए एक नीतिगत चुनौती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर एक अलग विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (रॉव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण जो की पूर्व में पंचवर्षीय (प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार) आधार पर किया जाता था, के आंकड़ा संग्रहण तंत्र और प्रतिचयन डिजाईन की सर्वेक्षण प्रणाली में कुछ बदलावों के साथ

2017-18 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) नामक एक नया नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आरंभ किया है । आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय संकेतकों के त्रैमासिक बदलावों का आकलन करने तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान को लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ।

प्रथम अनुमानों के आधार पर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से उपलब्ध बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति में 6.1 प्रतिशत है, जो कि 31 मई 2019 को जारी की गयी है ।

(ग) और (घ): पीएलएफएस के परिणाम सम्पूर्ण देश के शिक्षा, आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर देश भर में नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों का वितरण बताते है तथा जिनको सरकार नीतियां बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सकती है । इसके अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है ।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2017 - जून, 2018) और त्रैमासिक बुलेटिन (अक्टूबर-दिसम्बर 2018) को 31 मई 2019 को जारी की गयी है ।

*****